International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(1): 143-146
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 13-02-2026
Accepted: 24-02-2026
Publish : 25-02-2026

डॉ. अरुणिमा मिश्रा
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक,
केंद्रीय विद्यालय संगठन

Correspondence:
डॉ. अरुणिमा मिश्रा
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक,
केंद्रीय विद्यालय संगठन

प्रभावी मूल्यांकन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भूमिका

डॉ. अरुणिमा मिश्रा

शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण विषय रहा है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन का अर्थ छात्रों को उत्तीर्ण (प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान) अथवा अनुत्तीर्ण के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया माना जाता रहा। वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा यह तय करती थी कि छात्र कितना बुद्धिमान है। यह प्रक्रिया छात्रों के रटने की क्षमता का आंकलन मात्र करती थी, जिसमें उनके अन्य कौशल एवं विशेषताएँ गौण हो जाते थे तथा उनके संवर्धन हेतु उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिल पाता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) इस मानसिकता के लिए सुधारात्मक पहल करती है। यह तय करती है कि छात्रों के समग्र विकास के साथ उनका समग्र मूल्यांकन भी हो सके। NEP 2020 स्पष्ट करती है कि मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य छात्र को डराना या उसे असफल घोषित करना नहीं, बल्कि उसकी सीखने की यात्रा का समर्थन करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सतत मूल्यांकन की बात करती है, जिसका अर्थ है कि मूल्यांकन केवल परीक्षा के दिनों में नहीं, बल्कि निरंतर कक्षा की गतिविधियों, चर्चाओं और प्रयोगों के माध्यम से होना चाहिए। मूल्यांकन की यह परिभाषा छात्रों एक चिंतनशील शिक्षार्थी के रूप में प्रोत्साहित करती है। NEP 2020 मूल्यांकन प्रक्रिया में समानता एवं वस्तुनिष्ठता लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की स्वीकृति प्रदान करती है। कुछ विद्यालयों में TARA, PRASHAST, PARAKH आदि A.I. आधारित उपकरणों का उपयोग भी किया जा रहा है। मूल्यांकन में सुधार की कोशिशें पहले भी हुई हैं, जिनमें 'सतत और व्यापक मूल्यांकन' (CCE) सबसे प्रमुख था। CCE का उद्देश्य भी छात्र का सर्वांगीण विकास था, लेकिन इससे शिक्षकों के लिए वास्तविक शिक्षण के बजाय 'डेटा एंट्री' पर जोर बढ़ गया। ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर छात्रों और अभिभावकों में स्पष्टता नहीं हो सकी। CCE के बावजूद, अंतिम परीक्षाएं याददाश्त पर आधारित थीं जिससे कोचिंग संस्थानों का प्रभाव कम होने की अपेक्षा और बढ़ने लगा।

NEP-2020 की विशेषताएँ

NEP-2020 उपरोक्त सीमाओं को पहचानती है और एक ऐसा ढांचा प्रदान करती है जो रचनात्मक मूल्यांकन को मुख्यधारा में लाता है। यह नीति जहाँ आवश्यक बदलाओं हेतु मार्गदर्शन करती है वहीं उसे प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी उपकरणों (जैसे PARAKH, TARA) आदि को भी उपलब्ध कराती है। NEP-2020 का महत्वपूर्ण पहल 360-डिग्री समग्र प्रगति कार्ड (Holistic Progress Card) है। यह वर्तमान मार्कशीट का एक उन्नत और मानवीय स्वरूप है।

➢ बहुआयामी विकास का मापन

पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड केवल 'संज्ञानात्मक' (Cognitive) पक्ष यानी गणित, विज्ञान या भाषा में मिले अंकों को दिखाता था। HPC छात्र के तीन प्रमुख क्षेत्रों का विवरण देता है:

संज्ञानात्मक पक्ष (Cognitive Domain) : विषयों का ज्ञान और वैचारिक स्पष्टता।

भावात्मक पक्ष (Affective Domain) : छात्र का व्यवहार, सहानुभूति, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता और भावनात्मक स्थिरता।

मनो-प्रेरणात्मक पक्ष (Psychomotor Domain) : शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प और व्यावहारिक कौशल।

➢ **मूल्यांकन के नवीन स्रोत**

HPC की विशिष्टता यह है कि इसमें केवल शिक्षक की राय नहीं होती। इसमें तीन स्तरों पर मूल्यांकन होता है:

स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment) : छात्र स्वयं अपनी प्रगति का विश्लेषण करता है। वह लिखता है कि उसने इस साल क्या नया सीखा और उसे कहाँ कठिनाई हुई। इससे छात्रों में सोचने की शक्ति विकसित होती है।

सहपाठी मूल्यांकन (Peer-Assessment) : छात्र के मित्र उसके सामाजिक व्यवहार और सहयोग की भावना पर फीडबैक देते हैं। यह बच्चों में टीम-भावना और एक-दूसरे के प्रति सम्मान पैदा करता है।

शिक्षक मूल्यांकन (Teacher-Assessment) : शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में छात्र के समग्र व्यक्तित्व का अवलोकन कर अपनी टिप्पणी दर्ज करता है।

➢ **योग्यता-आधारित मूल्यांकन :**

NEP-2020 का सबसे बड़ा प्रभाव रटने की पद्धति (Rote Learning) पर है। नीति का मानना है कि यदि छात्र ने न्यूटन के नियम रट लिए हैं लेकिन वह उसके व्यावहारिक पक्ष को नहीं जानता कि वे कार के ब्रेक में कैसे काम करते हैं, तो वह शिक्षा व्यर्थ है। योग्यता-आधारित मूल्यांकन का अर्थ है कि परीक्षा में प्रश्न सीधे किताब से नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न केस स्टडी (Case Studies) या परिस्थिति-आधारित (Situation-based) होंगे।

सफल (SAFAL) - एक मानक उपकरण

सीबीएसई (CBSE) और केंद्रीय विद्यालयों में लागू SAFAL (Structured Assessment for Analysing Learning) इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कक्षा 3, 5 और 8 में आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों और शिक्षकों को यह बताना है कि शिक्षण की पद्धति में कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करता है कि छात्र ने उस स्तर की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता (FLN) प्राप्त कर ली है जो उसके भविष्य के विकास के लिए अनिवार्य है। योग्यता-आधारित मूल्यांकन छात्र को केवल परीक्षा के लिए तैयार नहीं करता, बल्कि उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाता है।

➢ **बोर्ड परीक्षाओं का पुनर्गठन: तनाव-मुक्त मूल्यांकन का मॉडल**

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में 'बोर्ड परीक्षा' शब्द अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक दबाव का प्रतीक रहा है। NEP-2020 इस दबाव को कम करने के लिए संरचनात्मक बदलावों का प्रस्ताव करती है।

'लो-स्टेक' (Low-stakes) परीक्षाओं की अवधारणा

NEP-2020 के अनुच्छेद 4.37 में कहा गया है कि "बोर्ड परीक्षाओं को उनके वर्तमान स्वरूप से अधिक लचीला बनाया जाएगा, जिसमें छात्रों की क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा, न कि महीनों तक रटने की उनकी क्षमता का। बोर्ड परीक्षाओं को 'निम्न-जोखिम' (Low-stakes) वाली परीक्षाओं के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा, जिससे छात्रों को साल में दो बार परीक्षा देने का अवसर मिलेगा—एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार (Improvement) के लिए, यदि छात्र चाहें।"

नीति के इस पहल से छात्रों के तनाव में कमी होगी, अनावश्यक कोचिंग संस्कृति में कमी आएगी और यदि किसी छात्र का प्रदर्शन एक बार खराब रहता है, तो उसके पास सुधार का मौका होगा।

विषय चयन और लचीलापन

अब छात्रों को कला, विज्ञान और वाणिज्य में नहीं बांटा जाएगा। यदि कोई छात्र भौतिकी (Physics) के साथ संगीत (Music) पढ़ना चाहता है, तो उसे इसकी अनुमति होगी। बोर्ड परीक्षाएं भी इसी लचीलेपन को अपनाएंगी, जहाँ छात्र अपनी पसंद के विषयों में अपनी दक्षता साबित कर सकेंगे।

➢ **प्रौद्योगिकी और मूल्यांकन: डिजिटल उपकरणों का एकीकरण**

आधुनिक युग में तकनीक के बिना प्रभावी मूल्यांकन संभव नहीं है। NEP-2020 मूल्यांकन प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग पर जोर देती है।

"अनुच्छेद 4.36. स्कूल के वर्षों के दौरान छात्र की प्रगति को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है, ताकि छात्रों को उनके प्रदर्शन और विशिष्ट रुचियों के आधार पर उनके भविष्य के करियर विकल्पों के बारे में इष्टतम (Optimal) निर्णय लेने में मदद मिल सके।"

"अनुच्छेद 23.6. शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में सुधार के लिए एआई (AI) आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। इसमें 'अडैप्टिव असेसमेंट' (Adaptive Assessment) टूल्स शामिल होंगे, जो छात्र के उत्तरों के आधार पर प्रश्नों के कठिनाई स्तर को स्वयं निर्धारित करेंगे, जिससे प्रत्येक छात्र की वास्तविक क्षमता का सटीक मूल्यांकन हो सके।"

AI आधारित प्रभावी मूल्यांकन के 3 प्रमुख स्तंभ

वैयक्तिकृत फीडबैक (Personalized Feedback): AI छात्र की उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करेगा जहाँ वह कमजोर है, जिससे शिक्षक उसे व्यक्तिगत सुधार के सुझाव दे सकेंगे।

निरंतर ट्रैकिंग (Continuous Tracking): यह केवल साल के अंत में नहीं, बल्कि पूरे साल छात्र के सीखने के ग्राफ का विश्लेषण करेगा।

करियर मार्गदर्शन (Career Guidance): छात्र की क्षमता और रुचियों के डेटा का विश्लेषण करके AI यह सुझाव देगा कि छात्र के लिए कौन सा करियर (जैसे विज्ञान, कला या व्यावसायिक शिक्षा) सबसे उपयुक्त है।

- **टी.ए.आर.ए. (TARA) और बुनियादी साक्षरता**

प्राथमिक स्तर पर, शिक्षकों के पास बच्चों के पढ़ने की क्षमता मापने का सटीक पैमाना नहीं होता था। 'तारा' (Teacher's Assistant for Reading Assessment) जैसे ऐप AI का उपयोग करके बच्चे के उच्चारण और प्रवाह का विश्लेषण करते हैं। यह शिक्षक को तुरंत फीडबैक देता है कि बच्चे को किस विशेष ध्वनि या शब्द में कठिनाई हो रही है।

- **प्रशस्त (PRASHAST) और समावेशिता**

प्रभावी मूल्यांकन वही है जो समावेशी हो। प्रशस्त ऐप के माध्यम से स्कूलों में उन बच्चों की पहचान की जा रही है जिन्हें सीखने में विशेष सहायता (CWSN) की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करता है कि मूल्यांकन की पद्धति हर बच्चे की विशिष्ट क्षमता के अनुरूप हो।

- **डिजिटल पोर्टफोलियो**

अब छात्रों का रिकॉर्ड केवल कागजी फाइलों में नहीं, बल्कि डिजिटल पोर्टफोलियो में सुरक्षित रहेगा। इसमें छात्र द्वारा साल भर किए गए बेहतरीन प्रोजेक्ट्स, वीडियो प्रेजेंटेशन और रचनात्मक कार्यों का संग्रह होगा, जो भविष्य में उच्च शिक्षा या रोजगार के समय उसकी वास्तविक क्षमता का प्रमाण बनेगा।

- **परख (PARAKH): मूल्यांकन के मानकों का निर्धारण**

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अलग-अलग राज्यों के शिक्षा बोर्डों (CBSE, ICSE, UP Board, Bihar Board आदि) के बीच मूल्यांकन के तरीकों में भारी अंतर था। इस विसंगति को दूर करने के लिए NEP-2020 ने परख (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development) की स्थापना की है।

- मानकों में एकरूपता (Standardization)- परख एक राष्ट्रीय मानक-निर्धारण केंद्र (Standard Setting Body) के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य सभी बोर्डों के लिए मूल्यांकन के समान दिशा-निर्देश तैयार करना है, ताकि एक राज्य के छात्र को दूसरे राज्य के छात्र की तुलना में मूल्यांकन पद्धति के कारण नुकसान न उठाना पड़े।
- नेशनल अचीवमेंट सर्वे (NAS) का संचालन- परख केवल छात्रों का ही नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करता है। यह समय-समय पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) आयोजित करता है, जिससे सरकार को यह पता चलता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा का स्तर क्या है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है।

- **संस्थागत ढांचा और शिक्षक की बदलती भूमिका**

मूल्यांकन के इन सभी बदलावों को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी अंततः शिक्षक और स्कूल प्रशासन की है।

- शिक्षक का सशक्तिकरण - अब शिक्षक की भूमिका एक मनोवैज्ञानिक और विश्लेषक की हो गई है। उसे यह समझना होगा कि यदि कोई बच्चा गणित में कम अंक ला रहा है, तो क्या वह उसके किसी अक्षमता जैसे- डिस्केलकुलिया (Dysca-lculia) के कारण है या केवल अभ्यास की कमी के कारण। इसके लिए निरंतर व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- स्कूल डेटा हब और विद्या समीक्षा केंद्र - प्रत्येक स्कूल अब एक बड़े डेटा नेटवर्क (NDEAR) से जुड़ा है। मूल्यांकन के परिणामों को विद्या समीक्षा केंद्रों पर ट्रैक किया जाता है। इससे प्रशासन को यह स्पष्टता मिलती है कि नीतिगत बदलावों का वास्तविक प्रभाव क्या पड़ रहा है।

- **कार्यान्वयन की चुनौतियाँ**

किसी भी नीति की सफलता उसके कार्यान्वयन (Imple-mentation) पर निर्भर करती है। NEP-2020 का मूल्यांकन मॉडल अत्यंत प्रगतिशील है, परंतु भारतीय भौगोलिक और सामाजिक परिवेश में इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती है।

- **डिजिटल आधारित चुनौती**

NEP-2020 TARA और AI आधारित मूल्यांकन की बात करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में आज भी बिजली और स्थिर इंटरनेट की कमी है। शहरी और संपन्न स्कूलों के छात्र इन डिजिटल टूल्स का लाभ उठा पाएंगे, जबकि संसाधनहीन स्कूलों के छात्र पिछड़ सकते हैं। यह मूल्यांकन में असमानता पैदा कर सकती है।

- **शिक्षकों का अनुकूलन और प्रशिक्षण**

दशकों से अंकों और लिखावट के आधार पर कॉपी जांचने वाले शिक्षकों के लिए अचानक 360-डिग्री समग्र मूल्यांकन करना कठिन है। शिक्षक को अब केवल एक परीक्षक नहीं, बल्कि एक डेटा विश्लेषक और मनोवैज्ञानिक की तरह व्यवहार करना होगा। इसके लिए देश के लाखों शिक्षकों को गहन और निरंतर प्रशिक्षण (CPD) की आवश्यकता है।

- **अभिभावकों की मानसिकता में बदलाव**

भारतीय समाज में नंबरों के आधार पर क्षमता के दावा करने वाली मानसिकता बहुत गहरी है। अभिभावक आज भी बच्चे की सफलता को केवल गणित और विज्ञान के अंकों से मापते हैं। जब तक समाज

समग्र प्रगति कार्ड में उल्लिखित सहयोग, सहानुभूति और कला जैसे गुणों को अंकों के बराबर महत्व नहीं देगा, तब तक यह बदलाव केवल कागजों तक सीमित रहेगा।

- **वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिगत दृष्टिकोण**

स्व-मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन में पक्षपात (Bias) की संभावना रहती है। यदि कोई छात्र अपने मित्र को अच्छे अंक दे दे या शिक्षक किसी छात्र के प्रति पूर्वाग्रह रखे, तो मूल्यांकन की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसे पारदर्शी बनाने के लिए कड़े मापदंडों की आवश्यकता है।

- **शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्य दबाव**

एक शिक्षिका के रूप में मेरा एवं मेरे सहयोगियों का यह अनुभव है कि AI एवं विभिन्न APPs आधारित मूल्यांकन गतिविधियाँ समय का अधिक व्यय करतीं हैं एवं यह इन्टरनेट की स्पीड पर भी निर्भर रहती है। इस मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के पास विद्यालय द्वारा कोई अतिरिक्त डिवाइस उपलब्ध नहीं कराया जाता। शिक्षकों को इसे अपने मोबाइल के द्वारा ही कार्यान्वित करना होता है ऐसे में डिवाइस स्टोरेज भी इसे प्रभावित करता है।

निष्कर्ष: भविष्य का भारत और मूल्यांकन का विजन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा में मूल्यांकन की पारंपरिक अंक-केंद्रित प्रणाली को बदलकर एक विकास-केंद्रित ढांचा प्रस्तुत करती है, जिसका मूल उद्देश्य छात्रों में आलोचनात्मक सोच और वास्तविक समझ विकसित करना है। यह नीति वैदिक काल की प्राचीन मूल्यांकन पद्धतियों जैसे निरंतर अवलोकन और शास्त्रार्थ से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक तकनीकी उपकरणों का समावेश करती है, जिसमें 360-डिग्री समग्र प्रगति कार्ड एक प्रभावी कदम है। मूल्यांकन अब संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनो-प्रेरणात्मक विकास का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। बोर्ड परीक्षाओं को लो-स्टेक बनाकर और छात्रों को वर्ष में दो बार परीक्षा का विकल्प देकर उनके मानसिक तनाव को कम करने का प्रयास किया गया है, जबकि परख पूरे देश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों के बीच मूल्यांकन के मानकों में एकरूपता ला रही हैं। डिजिटल इंडिया के दौर में तारा और प्रशस्त जैसे ऐप्स बुनियादी साक्षरता और समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, जो शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की सीखने की जरूरतों को समझने में मदद करते हैं। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल चुनौती, शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता और समाज में अंकों के प्रति पारंपरिक धारणा जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, जिनका समाधान होने पर ही NEP-2020 के प्रस्तावना में वर्णित एसडीजी 4, भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों तथा 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों को धरातल पर उतार सकेगी। यह मूल्यांकन प्रणाली छात्र को केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार करने वाली एक दूरदर्शी पहल है।

सन्दर्भ सूची

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
- National Curriculum Framework for School Education, (2023), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।
- Manual on Competency-Based Assessment (SAFAL), (2021), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
- Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development, (2023), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।
- NIPUN Bharat Mission (2021): Guidelines for Foundational Literacy and Numeracy (FLN), स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय।
- अग्रवाल, आर.के. (2022): Indian Education System and NEP 2020, प्रभात प्रकाशन।
- सैनी, जे.एस. (2021): Competency-Based Education and Assessment: A New Paradigm, पब्लिकेशन डिवीज़न।
- DIKSHA Portal
- PRASHAST App Guidelines: NCERT द्वारा दिव्यांगता स्क्रीनिंग टूल के दिशा-निर्देश।